



शैल

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

साप्ताहिक
समाचार

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 48 अंक - 44 पंजीकरण आरएनआई 26040 / 74 डाक पंजीकरण एच. पी. / 93 / एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 6 - 13 नवम्बर 2023 मूल्य पांच रुपये

प्रदेश को चार वर्षों में आत्मनिर्भर और दस में सबसे अमीर बनाएंगे—सुख्ख्

शिमला / शैल। देवी देवताओं के आशीर्वाद और जनता की दुआओं से स्वस्थ होकर लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्ख् का शिमला पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों और जनता ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय आराम करने और समय पर खाना खाने की सलाह दी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते रहेंगे क्योंकि चार वर्षों में प्रदेश को आत्मनिर्भर और दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री का यह संकल्प प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिये एक बड़ी चुनौती होगा क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो दस गारंटीयां प्रदेश की जनता को दी थी उन पर अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये जा सके हैं। बल्कि इन गारंटीयों के बाद सरकार के सौ दिन पूरे होने पर कुछ और वायदे भी प्रदेश की जनता से मार्च माह में किये गये हैं। इस समय भाजपा इन गारंटीयों को लेकर सुख्ख् सरकार के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक हुई पड़ी है। भाजपा का हर नेता इसे मुद्दा बना कर हर दिन उछाल रहा है। चुनावी राज्यों में भी यह गारंटीयां मुद्दा बनी हुई हैं।

दूसरी और सुख्ख् सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से 9200 करोड़ की देनदारियां विरासत में

- ✓ क्या कर्ज की बैसारियों पर चल रहे प्रदेश के लिये यह संभव हो पायेगा?
- ✓ क्या मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने यह वायदा करवाने से पहले जमीनी हकीकत का संज्ञान नहीं लिया है

मिली है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की सीमा में भी काफी कटौती की है। यह



आरोप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर लाये गये श्वेत पत्र में दर्ज है। ऐसी कठिन वित्तीय स्थिति से गुजरती हुई सरकार अब तक 11000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और 800 करोड़ लेने की प्रक्रिया में है।

और दस वर्षों में देश का सबसे वित्तीय स्थिति पर लाये गये श्वेत पत्र में दर्ज है। ऐसी कठिन वित्तीय स्थिति से गुजरती हुई सरकार अब तक 11000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और 800 करोड़ लेने की प्रक्रिया में है।

पूरा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि इस समय प्रदेश में कितनी व्यवहारिक शक्ति ले पायेगा इसको लेकर साथ ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि सरकार की कार्यशैली और उसकी अब तक की

वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सरकार में सौ दिन पूरा होने पर सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में जो रोजगार की उपलब्धता का आंकड़ा जारी किया था वह वायदा कागजी आश्वासन से आगे नहीं बढ़ पाया है।

इस वस्तुस्थिति में स्वास्थ्य लाभ लेकर लौटे मुख्यमंत्री से इतना बड़ा और वायदा करवा देना विषय को एक और मुद्दा देना बन जायेगा। स्वभाविक है कि सलाहकारों द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ऐसा व्याप्त जारी करवा देना अपने में ही कई सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि अब तक की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट हो गया है की सरकार को हर माह एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में कर्ज लेकर वायदों को पूरा करना किसी भी गणित में से प्रदेश हित में नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों का सामना करना पड़ेगा। उस समय यह कर्ज और वायदे जनता के सबसे बड़े सवाल होंगे। विषय इनको लेकर पूरी तरह हमलावर होगा। क्या कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इन सवालों का जवाब दे पायेगा? विश्लेषकों का मानना है कि जो जनता मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थनाएं कर रही थी उसके सामने फिर ऐसे वायदे परोसने का कोई औचित्य नहीं था। इन वायदों पर प्रदेश संगठन और हाईकमान तक को जवाबदेह होना पड़ेगा यह तय है।

मुख्यमंत्री ने टूटीकड़ी बालिका आश्रम में बच्चों के साथ मनाई दीवाली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू ने जिला शिमला के बालिका आश्रम टूटीकड़ी में बच्चों के साथ दीवाली का उत्सव मनाया तथा उन्हें मिठाई, फल और पटाखे वितरित किए।

दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून बनाकर अनाथ बच्चों को

उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान



चिल्हन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति की प्रतीक है। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भन्ना प्रदान किया जा रहा है। उनकी

की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा 'आप माता - पिता के बिना नहीं हैं। राज्य सरकार ही आपकी माता और पिता है। इसलिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते आपके साथ दीवाली मनाने आया है। दीवाली का पर्व आपके जीवन में खुशियां लाये और राज्य सरकार भी इसी सोच के साथ कार्य कर रही है। जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करें क्योंकि चुनौतियाँ ही आत्मविश्वास पैदा करती हैं और जीवन को दिशा देती हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू ने

कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार एकल नारियों तथा मूक - बधिर बच्चों के लिए भी योजना लाने वाली है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ इन योजनाओं में सुधार भी किया जाएगा।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले बालिका आश्रम टूटीकड़ी आए, जो ऐतिहासिक है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आपदा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान किया है, जिनकी भरपाई करने में वक्त लगेगा। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार ज्ञालामुखी और सुंदरनगर में अनाथ बच्चों के लिए दो स्टेट ऑफ द आर्ट आश्रम बनाने जा रही हैं, जिनकी आधारशिला जल्द ही करेगी। उन्होंने सभी को दीवाली की शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विद्यायक हरीश जनार्था, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, आओडी रितेश कपरेट, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग रुपाली ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में मनाई दीवाली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आम लोगों के

दीवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए सुख - समृद्धि की कामना



साथ दीवाली पर्व मनाया।

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा आम लोगों ने उन्हें

मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत 25 नवम्बर तक कर सकेंगे आवेदन

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मेधा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सत्र 2023 - 24 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन आमत्रित किए गए हैं। उन्होंने

कहा कि इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए 25 नवम्बर, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिगत बारहवीं कक्षा तक के छात्र - छात्राएं अपना आवेदन संबंधित जिला के उच्चतर शिक्षा उप - निदेशक के पास डाक द्वारा अथवा ई - मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। स्नातक स्तर के छात्र - छात्राएं अपना आवेदन पत्र अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक (कॉलेज), शिक्षा निदेशलय के पास डाक अथवा ई - मेल medha.protsahan@gov.in पर उपलब्ध है।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि योजना के तहत कोचिंग संस्थानों को उच्चतर शिक्षा विभाग को एक लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करवानी अनिवार्य है। यदि अभी तक किसी संस्थान द्वारा यह राशि जमा नहीं की गयी तो उन्हें यह तुरन्त प्रभाव से यह जमा करवानी होगी और तभी वह कोचिंग संस्थान इस उद्देश्य के लिए पात्र होगा।

मुख्य निर्वाचित अधिकारी ने उपायुक्तों द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्त) द्वारा की जा रही प्रारम्भिक तैयारियों का वीडियो कानप्रेसिंग के माध्यम से जायजा लिया। इस सन्दर्भ में मुख्य निर्वाचित अधिकारी ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को मानव संसाधन तथा भण्डारण और पारगमन के संसाधनों की समय रहने पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा - निर्देश दिये।

उन्होंने मतदान के संचालन के लिए गठित किये जाने वाले मतदान दलों तथा उनके गन्तव्य तक प्रस्थान करने तथा मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली वैबकास्टिंग हेतु वाछित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से सम्पर्क करने के भी निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचित अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान व्यय नियंत्रण के लिए स्थाई व्यय नियंत्रण कमेटी गठित करने तथा व्यय संवेदनशील पॉकेट की पहचान करने सम्बन्धित विस्तृत निर्देश दिये।

उन्होंने मतदाता सूचियों में 18 - 19 वर्ष के पात्र मतदाताओं के बहुत कम संख्या में पंजीकरण पर करने पर बल दिये।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचित अधिकारी दलीप नेहीं तथा नीलम दुल्ला सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 144.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

शिमला/शैल। ग्रामीण स्तर तक तीव्र विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। विकेन्ड्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसके बजट में बढ़ोत्तरी की है। प्रदेश में इस वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। इसके लिए 144.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इस वित्त वर्ष के लिए किया गया है, जिसमें से 15 अक्टूबर, 2023 तक 74.84 करोड़ रुपये दो किश्तों में जिलों को जारी किए जा रहे हैं। भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत सरकार ने इस योजना के दिशा - निर्देशों में संशोधन किया है। इसे व्यापक रूप प्रदान करते हुए इसके अन्तर्गत रिटेनिंग तथा ब्रेस्ट दिवारों की मुरम्मत एवं नालों के तटीयकरण का भी प्रावधान किया गया है।

वर्षावार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 - 20 में इस योजना के अन्तर्गत 97.98 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020 - 21 में

रख - रखाव, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मरम्मत, इन क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत व रख - रखाव, सामुदायिक वाई - फाई लगाने, लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर व कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना भी इसमें शामिल है। योजना के तहत पंजीकृत महिला मण्डलों को बर्तन व फर्नीचर तथा युवक मण्डलों को खेल उपकरण, स्वयं सहायता समूहों को भी इन मदों में अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति मण्डल अथवा समूह अनुदान का प्रावधान है। शहीदों के बलिदान की समृद्धि में शहीदी द्वारों का निर्माण भी इस योजना के तहत करवाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू का कहना है कि प्रदेश सरकार अन्तिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प है। ग्रामीण स्तर पर विधायकों के माध्यम से विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का

हमे ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

किसके पक्ष में जाएंगे यह चुनाव परिणाम



पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे यह तो परिणाम आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पायेगा। लेकिन जिस तरह राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक दलों का सामने आता जा रहा है उससे यह संकेत उभर रहे हैं कि इन चुनावों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। भाजपा का यह नुकसान कांग्रेस का ही लाभ रहेगा यह पूरी स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरे दल भी चुनाव में हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह परिणाम देश की राजनीति पर एक गहरा और दुर्गमी प्रभाव डालेगे। क्योंकि इस समय देश 1975 के आपातकाल जैसी स्थितियों से गुजर रहा है। उस समय का आपातकाल घोषित था और आज का अघोषित है। वह आपातकाल 1975 में शुरू होकर 1977 के आम चुनाव में समाप्त हो गया था। परन्तु आज का आपात 2014 के सत्ता परिवर्तन से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है। उस समय के आपातकाल में देश की आर्थिकी मजबूत हुई थी और आज के अघोषित आपात में आर्थिकी ही सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से सारे अदारे निजी क्षेत्र के हवाले कर दिये गये हैं। इसमें आम आदमी के हिस्से में केवल कर्ज आया है। 2014 के सत्ता परिवर्तन के समय केंद्र सरकार का कुल कर्ज 55000 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। राज्य सरकारों का ही कर्ज 70 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। जिस अनुपात में कर्ज बड़ा है उसी अनुपात में महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ी है। सत्ता परिवर्तन से लेकर अब तक जो कुछ घटा है वह सब आज चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार को अपनी अब तक की सारी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रशासन के सहयोग से आयोजित करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर देश के सामने एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जहां प्रत्येक नागरिक को भविष्य के हित में एक सुविचारित फैसला लेने की घड़ी आ गई है। इस फैसले के लिए यह ध्यान में रखना होगा कि यदि आर्थिकी बची रहेगी तो दूसरी चीजें देर सवेर संभल जायेंगी। इस समय सत्ता जिस तरह से आर्थिकी के सवाल को मन्दिर-मस्जिद और हिन्दू-मुस्लिम के आवरणों से ढकने का प्रयास कर रही है क्या वह किसी भी गणित से एक लाभकारी प्रयोग हो सकता है। आज जिस देश की आधी से अधिक आवादी को सरकार के मुफ्त राशन पर जीने के कगार पर पहुंचा दिया गया हो उस देश का भविष्य क्या होगा यह सोचने का विषय है। जिन नीतियों और योजनाओं के कारण महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बड़ा हो क्या उसका समर्थन किया जा सकता है। इस समय हर राज्य सरकार का आकलन कर्ज और मुफ्ती के बिन्दुओं पर करना होगा चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो। क्योंकि मुफ्ती के वायदे केवल कर्ज के सहारे ही पूरे किये जा सकते हैं और बढ़ता कर्ज किसी भी विकास का कोई मानदण्ड नहीं होता है। इसलिए इन चुनावों में मतदाताओं को इन बिन्दुओं का आकलन करके ही मतदाता का फैसला लेना होगा।

भाजपा की रणनीति सफल रही तो इंडिया गठबंधन के कई दल होंगे मोदी के साथ



गौतम चौधरी

आगामी 2024 के संसदीय आम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा और भाजपा की रणनीति सफल रही, तो इंडिया गठबंधन में फूट तय है। यही नहीं आम चुनाव के बाद विपक्षी एकता के नाम पर एकत्र हुए दल अपने - अपने हितों के लिए भाजपा के साथ समझौता कर लेंगे। एक बार फिर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके घटक दलों में तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और भारत राष्ट्र समिति शामिल होंगे। भाजपा के रणनीतिकार इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके लक्षण भी दिखने लगे हैं। हालांकि इन पार्टियों को यह भी डर है कि यदि वे भाजपा के साथ जाते हैं तो उनके साथ जो भाजपा विरोधी मुस्लिम या अल्पसंख्यकों का वोट है वह कट जाएगा। इसलिए चुनाव से पहले ये तमाम पार्टियां भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल भी नहीं होगी लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनाने की बात होगी ये पार्टियां प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर देंगी।

विगत दिनों भाजपा के एक केंद्रीय नेता ने इस संदर्भ में कुछ गंभीर बातें बताई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी आम चुनाव बाद क्या रणनीति अपनाने बाली है लेकिन इशारों में ऐसा कुछ कहा जो राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह अधिनायकवाद में विश्वास नहीं करती है। साथ ही क्षेत्रीय दलों के अहमियत को

भी समझती है। देश के कई समाजवादी धरे वाले क्षेत्रीय दलों के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने बताया कि वैसे तो इस बार भी बहुमत हमारी ही होगी। राजनीति का कुछ कहा नहीं जा सकता है। विपरीत परिस्थिति बनी और सरकार बनाने के लिए यदि कुछ सांसद कम पड़ गए तो हम नये दोस्त भी बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने नए दोस्तों में किसी दल का नाम नहीं लिया लेकिन बार-बार प्रवर्तन निदेशालय के समन जारी होने के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होना, लालू प्रसाद यादव परिवार पर केन्द्र सरकार की विशेष कृपा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में ढील और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंतला कविता के दो खास सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद भी उसके उपर कोई कारवाई नहीं होना, यह साबित करता है कि भाजपा और इन क्षेत्रीय दलों के बीच कोई खास प्रकार की राजनीतिक खिचड़ी पक रही है।

बता दें कि इस बार भाजपा विशेष संकट में है। इस बार केवल विपक्षी दलों से ही भाजपा को चुनौती नहीं मिल रही है अपितु अपने संगठन परिवार के सहयोगी भी भाजपा से कन्नी काट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शीत युद्ध जारी है। इसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसके कारण मोदी-शाह के संरक्षण और डॉ. जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव महसूस कर रही है। इसका असर अभी हाल ही में संपन्न कुछ राज्य के चुनाव में भी देखने को मिला। खास कर कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश की हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है। अभी चल रहे पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। तेलंगाना,

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का चुनाव 2024 के संसदीय आम चुनाव का लिटमसप्टर टेस्ट है। यदि इन राज्यों में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई तो न केवल मोदी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा होगा अपितु आगामी संसदीय चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का चेहरे पर भी विवाद खड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में मोदी को खुद के बल पर आगामी चुनाव और सरकार दोनों को संभालना पड़ेगा।

जानकारी में रहे कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा की बड़ी भूमिका थी। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि जब केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तो बिहार में कभी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर नहीं किया गया। यही नहीं कई मौके पर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लालू यादव को सहयोग भी किया। नीतीश के बगावत के बाद भाजपा बिहार में लालू यादव पर लगातार डेरे डाल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तो झारखंड में भाजपा सरकार तक चला चुकी है। उसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस कभी भाजपा की सहयोगी पार्टी रह चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ भी भाजपा के मध्यर संबंध रहे हैं।

इस प्रकार भाजपा अब अच्छी तरह समझ गयी है कि एकला चलो से काम चलने वाला नहीं है। यदि केन्द्र में फिर से सत्ता प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन में अविश्वास पैदा करना होगा। इस रणनीति में भाजपा कामयाब होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के खिलाफ व्यानबाजी पर उत्तर आए हैं। लोकसभा चुनाव आते - आते इंडिया गठबंधन का दरार और बढ़ेगा। भाजपा इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। साथ ही रणनीति के तहत काम हुआ तो इंडिया गठबंधन के कई साथी नरेन्द्र मोदी की तिहरी ताजपोशी में सहयोगी भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लेप्पा में बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के लेप्पा में बहादुर जवानों को संबोधित किया।

जवानों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली के त्योहार और जवानों के साहस की प्रशंसा का मेल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ज्ञान का एक क्षण है। उन्होंने भारत के सीमावर्ती इलाके पर स्थितदेश के आखिरी गांव, जिसे अब पहला गांव माना गया है, में तैनात जवानों के साथ देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी।

अपने अनुभवों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सव वहीं होता है जहां परिवार रहता है। उन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए त्योहार के दिन अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति को कर्तव्यों के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने की भावना सुरक्षाकर्मियों के उद्देश्यों को सार्थकता प्रदान करती है। उन्होंने कहा, 'देश इसके लिए आपका आभारी और छट्टी है। इसीलिए हर घर में आपकी सुरक्षा के लिए एक 'दीया' जलाया जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'जहां जवान तैनात हैं वह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। आप जहां भी हैं, मेरा त्योहार वहीं है। ऐसा शायद 30-35 वर्षों से चल रहा है।'

सशस्त्र बलों ने भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है युद्ध क्षेत्र से लेकर बचाव अभियान तक, भारतीय सशस्त्र बल जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं

देश की रक्षा में नारीशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है

प्रधानमंत्री ने जवानों और सशस्त्र बलों की बलिदान की परंपरा को नमन किया। उन्होंने कहा, 'हमारे बहादुर जवानों ने खुद को सीमा पर सबसे

भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों का भी उल्लेख किया जहां सशस्त्र बलों ने अनेक लोगों की



मजबूत दीवार के रूप में साबित किया है।' प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'हमारे बहादुर जवानों ने हार के जबड़े से जीत को छीनकर हमेशा नागरिकों का दिल जीता है।' उन्होंने

जान बचाई है। उन्होंने कहा, 'सशस्त्र बलों ने भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।' प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों के लिए एक स्मारक हाल के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसे सर्वसम्मति से

संचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक 'डिजिटल विज्ञापन नीति' 2023 को स्वीकृति दी

नीतिगत प्रारूप डिजिटल युग में व्यापक सरकारी पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगा

शिमला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार व्यारों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी 'डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023' को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संचार व्यारों डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है। यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने एवं जागरूकता जगाने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण अभियान को चिह्नित करती है।

यह नीति डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक कोंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता भी लायी जा सकेगी। हाल के वर्षों में, दर्शकों को मीडिया उपयोग को देखते हुए इसमें डिजिटल क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल

आधार में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है।

यह नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी। सीबीसी, डिजिटल ऑटिडियो प्लेटफार्मों के पैनल के माध्यम से पॉडकास्ट और डिजिटल ऑटिडियो प्लेटफार्मों पर श्रोताओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा। इंटरनेट वेबसाइटों को सूचीबद्ध करने की अपनी प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के अलावा, सीबीसी अब प्रथम बार अपने सार्वजनिक सेवा अभियान संदेशों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी प्रसारित करने में सक्षम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म सार्वजनिक वार्तालाप के लोकप्रिय चैनलों में से एक बनने के साथ, यह नीति उस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करती है जिसके माध्यम से सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिनके माध्यम से व्यापक स्तर पर एक निकारात्मक और वीडियो तैयार किए जाते हैं और इनकी पहुंच हैंडल के ग्राहकों तक ही सीमित है। सरकारी मंत्रालयों और विभागों की इस पहुंच को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई, केंद्रीय संचार व्यूरो द्वारा सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए नामित संगठन तक बढ़ाया जाएगा। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 कई हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है और यह भारत सरकार की डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और नागरिकों तक सूचना-प्रसार में सुधार के प्रारूप की रूपरेखा तैयार करती है।

केंद्रीय संचार व्यूरो (सीबीसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य का संचालन करता है और भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता जगाने और जानकारी प्रसारित करने का दायित्व संभालता है। सीबीसी बदलते में योजनाओं को संबोधित करने के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का भी अधिकार प्रदान करती है।

यह नीति डिजिटल परिदृश्य की

गतिशील स्थिति को समझते हुए सीबीसी को विधिवत गठित समिति की स्वीकृति के साथ डिजिटल स्पेस में नये और अभिनव संचार प्लेटफार्मों में शामिल होने का अधिकार प्रदान करती है। सीबीसी की डिजिटल

दिया कि जब तक इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, यह देश बेहतर भविष्य की दिशा में प्रयास करता रहेगा। उन्होंने भारत के विकास का श्रेय सशस्त्र बलों की शक्ति, संकल्प और बलिदान को दिया।

इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि भारत ने अपने संघर्षों से संभावनाएं पैदा की हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व विकास और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की सेनाओं व सुरक्षा बलों की शक्ति लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि कैसे देश पहले अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, जबकि आज वह मित्र देशों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2016 में प्रधानमंत्री के इस क्षेत्र के दौरे के बाद से भारत के रक्षा निर्यात में आठ गुना से अधिक की वृद्धि हो गई है। उन्होंने कहा, 'देश में आज एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का रक्षा उत्पादन हो रहा है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।'

प्रधानमंत्री ने उच्च-तकनीक पर आधारित प्रौद्योगिकी एं सीडीएस जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के समन्वय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लगातार और अधिक आधुनिक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अब निकट भविष्य में ज़रूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी के इस बढ़ते प्रसार के बीच, मोदी ने सशस्त्र बलों से प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्रम में मानवीय समझ को हमेशा सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को कभी भी मानवीय संवेदनाओं पर हावी नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज स्वदेशी संसाधन और उच्च श्रेणी का सीमा संबंधी बुनियादी ढांचा भी हमारी ताकत बन रहे हैं। और मुझे खुशी है कि नारीशक्ति भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है।' उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान हासिल हुई विभिन्न वैश्विक एवं लोकतात्रिक उपलब्धियों के बारे में बताया और चंद्रयान लैंडिंग, आदित्य एला, गगनयान से जुड़े परीक्षण, स्वदेशी विमानवाहक पोता आईएनएस विक्रांत, तुम्हकुर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, वाइब्रेंट विलेज अभियान और खेलों से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया। पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल हुई विभिन्न वैश्विक एवं लोकतात्रिक उपलब्धियों को आगे गिनाते हुए, प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन, नारीशक्ति वंदन अधिनियम, जी-20, जैव ईंधन गठबंधन, दुनिया भर में वास्तविक समय में भगतान संबंधी सुविधा के उत्कर्ष, निर्यात के क्षेत्र में 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 5जी की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'पिछला वर्ष राष्ट्र निर्माण के मामले में एक उपलब्धि-भरा वर्ष रहा।'

उन्होंने कहा कि भार

दीपावली पर मुख्यमंत्री सुख आश्रय कांग्रेस के नेता अन्य प्रदेशों में 10 गरंटी पूरी करने का झूठ प्रचार कर रहे हैं: जयराम

देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को जारी किया 5.27 लाख रुपये का उत्सव भत्ता

शिमला / शैल। इस दीपावली पर जब प्रदेश भर में माँ लक्ष्मी की आराधना में लाखों दिए जलाये जाएंगे तो इनमें कई ऐसे दिए भी होंगे जो प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदान किये जा रहे उत्सव भत्ते के कारण रोशन होंगे। जब प्रदेश के लाखों घरों में खुशियों की फुलझड़ियां जल रही होंगी तो कई चेहरे इसलिए खिल रहे होंगे क्यूंकि वो अब निराश्रित नहीं बल्कि 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' हैं यानी कि प्रदेश सरकार उनकी माता और पिता है। इस बार बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों के आँगन में भी दिए जगमगाएंगे, पटाखे फूटेंगे और मिठाइयां बटेंगी। वह भी दीपावली उत्सव धम-धाम से मनाएंगे। यह सब संभव ही पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू के संवेदनशील नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखविंदर योजना के कारण।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों ('चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट') को दीपावली पर्व पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपये व बाल देखभाल संस्थानों को 3,27,500 रुपये जारी किये थे। इन त्यौहारों पर सरकार द्वारा कुल 17,09,000 रुपये जारी किए गए हैं।

दीपावली के उत्पाद्य पर 3,27,500 रुपये जारी किये गए हैं ताकि इन संस्थानों में भी इस त्यौहार से सम्बन्धी सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। सरकार द्वारा सभी 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को त्यौहारों पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति बच्चा प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा उन बाल देखभाल संस्थानों को, जिनमें बच्चों के रहने की क्षमता 25 या इससे कम हो, उन्हें 5,000 तथा 25 से अधिक की क्षमता वाले बाल देखभाल संस्थानों को 10,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं।

इससे पर्व राज्य सरकार ने दशहरा उत्सव पर भी उत्सव भत्ते के रूप में इन बच्चों को 5,27,000 रुपये व बाल देखभाल संस्थानों को 3,27,500 रुपये जारी किये थे। इन त्यौहारों पर सरकार द्वारा कुल 17,09,000 रुपये जारी किए गए हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुकरू ने सरकार के गठन के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय में समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी। मानवीय संवेदनशीलों को अधिमान देते हुए इसके अनाश बच्चों और अन्य सरकार ने अनाश बच्चों और अन्य

जाइका प्रोजेक्ट से शीत मरुस्थल में आ रही हरियाली

प्रदेश के शीत मरुस्थल क्षेत्रों में हरियाली लाने के लिए जाइका परियोजना की पहल का परिणाम सामने आने लगा है। ऐसे में जाहिर है कि जाइका प्रोजेक्ट



से शीत मरुस्थल में हरियाली आने लगी है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका वानिकी परियोजना के तहत जिला किन्नौर के श्यासो गांव में 76 हजार लीटर की क्षमता वाला सिंचाई जल भंडारण टैक्ट तैयार किया गया। इस कठिन एवं शीत भौगोलिक परिस्थिति के दायरे में आने वाले इस गांव की जनता के जज्बे को भी सलाम करना होगा। यह इसलिए कि वहां की जनता ने श्रमदान के माध्यम से एक लाख के अतिरिक्त बजट को कवर किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जाइका प्रोजेक्ट के तहत 76 हजार लीटर वाटर स्टोरेज टैक्ट के होने से पौधरोपन के बाद उन्हें सींचने में पानी की कमी नहीं सताएगी। इसके साथ-साथ इस वाटर स्टोरेज टैक्ट का लाभ वहां के लोगों की भूमि सुधार में भी मिलेगा। यही नहीं, बल्कि यहां कृषि योग्य भूमि पर कृषि भी हो पाएगी। जाइका प्रोजेक्ट के माध्यम से जल भंडारण टैक्ट बना तो लोगों ने खेतों तक सिंचाई जल की सालाई के लिए कुहलों का निर्माण भी कर दियावाया। इस परियोजना के तहत वहां की महिलाओं की आर्थिकी के सुधार के लिए स्वयं

- डा. सुशील काप्टा,
वानिकी एवं जैव विविधता
विशेषज्ञ, जाइका।

सहयोगी एवं मरुस्थल का गठन कर प्रशिक्षण का आयोजन एवं मशीनरी खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। बता दें कि इस गांव में इससे पहले सिंचाई के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जाइका परियोजना ने यहां टैक्ट निर्माण कर किसान एवं बागवानों को बेहतर सुविधा दी।

जाइका वानिकी परियोजना के तहत जिला किन्नौर के श्यासो गांव में निर्मित जल भंडारण टैक्ट से अब वहां के किसान एवं बागवानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा भी मिल रही है। गौरतलब है कि किन्नौर का श्यासो गांव काफी दुर्गम है और यहां बारिश न होने के कारण किसान एवं बागवानों को सिंचाई में काफी दिक्कतें आती हैं। हालांकि यहां कृषि एवं बागवानी लोगों की आर्थिकी का मुख्य साधन है, लेकिन सिंचाई के पानी की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानियां होती थी। मगर जब से जाइका प्रोजेक्ट से यहां 76 हजार लीटर की क्षमता का टैक्ट तैयार किया गया तब उसके बाद यहां के किसान एवं बागवानों की तकदीर बदलने लगी है।

हाल ही में हमारी टीम ने जिला किन्नौर के श्यासो गांव में निर्मित 76 हजार लीटर की क्षमता के जल भंडारण टैक्ट का निरीक्षण किया। जाइका परियोजना के तहत क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से यहां के लोगों में काफी उत्साह है, जाइका परियोजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। दूरदराज गांव श्यासो में वाटर स्टोरेज टैक्ट होने से यहां के किसान एवं बागवानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी।

शिमला / शैल। भाजपा नेता

प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला

कि सभी गरंटीयां पूरी हो गई हैं। मेरा

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाना हुआ



रिज मैदान के पीआईबी की एक प्रदर्शनी में समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 वर्ष अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। भारत ने हर क्षेत्र में तरकीबी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेतृत्व वाला है। पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेतृत्व वाला है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक भागीदारी की विजय की तरीकी से किये थे और वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रचार कर रखा है कि जितने भी वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किये थे सभी पूरी कर दिये।

हमें यह समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के नेता सब कब बोलेंगे, हमेशा ब्रूठ के बलबूते पर ही राजनीति चलाते हैं।

उन्होंने कहा कि इडी गठबंधन बनने से पहले ही विभाजन की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में उनके एक नेता ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब इसी गठबंधन के नेता उस नेता से तनी काट रहे हैं। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इस गठबंधन का आने वाले समय में कोई भविष्य नहीं है।

मुफ्त राशन देकर पीएम मोदी ने जनता को दिया तोफ़ा: बिंदल

शिमला / शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने



80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का कार्य पिछले 3 साल से किया और अब दीपावली पर पीएम मोदी ने इस योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ा दिया इसके लिए पीएम मोदी का आभार।

केंद्र सरकार ने जनता को हमारी राहत देने का कार्य किया है, सस्ते दाम का आटा घर-घर पहुंचेगा जो की एक केंद्र सरकार की प्रदेश जनता को बढ़ा देने की दर से मिलेगी।

बिंदल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डीजल में 7 रु की कटौती की थी, जो कि कांग्रेस ने आते ही बढ़ा दी और डीजल को 7 रु महंगा कर दिया, इससे हिमाचल की जनता पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा है और इससे महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी कर, तरह-तरह के टैक्स लगाकर हर चीज का दाम बढ़ाने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है। यहां तक की बसों में भी तरह-तरह की टिकट लगाकर जनता को परेशान करने का कार्य प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी गरंटियों के उल्टा कार्य कर रही है यह कांग्रेस सरकार।

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिले के रामपुर बुशहर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि लवी एक व्यावसायिक मेले के साथ - साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ - साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मेला अनेकों संस्कृतियों का मिलन है। विभिन्न राज्यों से आये सांस्कृतिक दल एक ही मंच पर देश की विविध संस्कृति दर्शाते हुये अनेकता में एकता के भव जो जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही वर्ष 1985 में रामपुर लवी मेले को अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का दर्जा दिया गया था। उन्होंने माँ भीमाकाली से प्रदेशवासियों की सुख - समृद्धि की कामना की।

राज्यपाल ने लवी मेले की समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेले में प्रदर्शित ऊनी

वस्त्र, सर्वे भेवे और अन्य पारंपरिक शिल्प और उत्पाद अद्वितीय हैं। मेले में पारंपरिक कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक भारत, श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत देश



के सभी राज्यों के स्थाना दिवस को राज भवन में आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को बढ़ाकर देश को एकता के सूत्र में पिरोया जा सके।

राज्यपाल ने इससे पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा मेला भैदान में लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया तथा इनमें गहरी स्थिर दिखाई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मेला समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय लवी

मेला - 2023 के लिए बनाये गये वीडियो टीजर का अनावरण भी किया।

इससे पहले उपायुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय लवी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष आदित्य नेगी ने राज्यपाल का स्वागत किया और मेले के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत



जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में शिमला, मंडी तथा सिरमौर जिला के लोकनृत्य दलों ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी दी।

इस अवसर पर रामपुर के विधायक नंदलाल, जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, उपमंडलाधिकारी रामपुर निःशांत तेमर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन में भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के स्थाना दिवस और राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ उपस्थित थीं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए 42 स्काउट्स एण्ड गाइड्स एण्ड

विश्व के करोड़ों युवा सम्बद्धित सेवा क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्था एवं विचारधारा की सदस्यता गर्व का विषय है और वैश्विक पटल पर 200 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अपने दैनिक तथा व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाया गया है। यह एक ऐसी संस्था है जिसके 5 करोड़ स्वयंसेवी सामाजिक सरोकारों एवं निःस्वार्थ सेवा



कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स वर्तमान युग में युवाओं के लिए मील पत्थर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से लाखों युवाओं ने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास किया है। यह संस्था भेदभाव से परे सभी स्वयंसेवकों के लिए समान अवसरों का सृजन करती है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नशा निवारण और नशे के समूल नाश के लिए युवाओं को एकजुट होकर

कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे की कुरीति को समाप्त करने के लिए अभिनव अभियान निश्चय आरम्भ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के सभी भागों में लोगों को इस कुरीति के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, ताकि इस कुरीति को समूल नाश किया जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस अभियान से बड़ी संरक्षा में लोग जुड़ कर नशे जैसी बुराई पर जीत हासिल करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से एक और अभियान की शुरूआत की जा रही है और नशे के विरुद्ध लड़ाई में गांव तथा पंचायत स्तर पर युवाओं के साथ - साथ जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नशे के विरुद्ध प्रदेश पुलिस के प्रयासों, विभिन्न जागरूकता अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज से नशे के समूल नाश के लिए सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है।

निदेशक, उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा ने भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के इडल्ट रिसोर्सिंज़ की राज्य आयुक्त अंजू शर्मा, उप - निदेशक उच्च शिक्षा लेख राज शर्मा और अन्य गणमान्य इस अवसर के लिए युवाओं को एकजुट होकर

सांसद प्रतिभा सिंह ने सामुदायिक भवन के निर्माण को दिए 3.50 लाख

क्षेत्र के अपने दौरे में उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी किया गया है।

इसी कड़ी में बीते कल जोगिन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये भी बीते कल 9 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। सांसद प्रतिभा सिंह ने 31 अक्टूबर को जोगिन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिये धनराशि मुहैया करवाने की घोषणा की थी। जिनमें लड्डूलौल के गांव गोरा बलोटू में पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन के बनने से आसपास के गांवों के सैकड़ों परिवारों को सुविधा मिलेगी।

सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि भीड़ संसदीय क्षेत्र के लोगों का विश्वास उनकी ताकत है। यहां विकास में कोई कोर कर सकते नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहने से वे उनकी समस्याओं और मांगों को अच्छे से समझती हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संसदीय

विधायक संजय रत्न ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। विधायक संजय रत्न ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस बाबत ज्वालामुखी विश्राम गृह में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक संजय रत्न ने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, तब तब विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ज्वालामुखी में उपमंडल कार्यालय, महाविद्यालय से लेकर कई विकास की योजनाएं इस विकास के लिए स्वीकृत करवाई हैं।

विधायक ने कहा कि लोगों के घरघास जाकर समस्याओं सुनना और उनका ध्येय है तथा जब भी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, तब तब विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ज्वालामुखी में उपमंडल कार्यालय, महाविद्यालय से लेकर कई विकास की योजनाएं इस विकास के लिए स्वीकृत करवाई हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों से किये वायदों को पूर्ण करना उनकी जिम्मेवारी है और चरणबद्ध इन्हें पूरा किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने के लिए भी विभागीय अधिकारी तत्परता के साथ कार्य करें ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो।

इस अवसर पर एसडीएम संजीव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सी.पी.एस. मामले पर शिमला से लेकर दिल्ली तक लगी निगाहें

शिमला/शैल। सी.पी.एस. मामला अब फिर प्रदेश उच्च न्यायालय में ही पहुंच गया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई थी कि पंजाब छत्तीसगढ़ और बंगाल की ऐसी ही याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए हिमाचल के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेकर उन मामलों के साथ सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का यह आग्रह यह कह कर ठुकरा दिया कि हिमाचल का मामला उनसे भिन्न है। इसलिए इसे प्रदेश उच्च न्यायालय ही सुनेगा। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट के लिए स्थानांतर का आग्रह प्रदेश उच्च न्यायालय में लगी पेशी से एक दिन पहले किया गया था। जबकि यह मामला कई दिनों से प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किये गये आग्रह को मामले को लम्बाने के प्रयास के रूप में देखा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया है तब यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? स्मरणीय है कि हिमाचल में एक बार पहले भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों को जब प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी तब उच्च न्यायालय ने इन्हें संविधान संशोधन के विपरीत प्रकार रद्द कर दिया था।

इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस फैसले के विवाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक एस.एल.पी. फाइल कर दी। एस.एल.पी. फाइल करने के बाद राज्य सरकार ने एक और अधिनियम लाकर ऐसी नियुक्तियों को लाभ के दायरे से बाहर करके पुनः ऐसी नियुक्तियों का रास्ता निकाल लिया। लेकिन सरकार के इस अधिनियम को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई जो अब तक लंबित चल रही है। लेकिन इसी मामले में प्रदेश सरकार ने जयराम सरकार के कार्यकाल में यह शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर कर रखा है कि यदि राज्य सरकार ऐसी नियुक्तियों करने का फैसला लेती है तो उसके लिये

- ✓ सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका अस्वीकार
- ✓ प्रदेश उच्च न्यायालय पहले भी रद्द कर चुका है ऐसी नियुक्तियां
- ✓ जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि प्रदेश विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं

उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति ली जायेगी ऐसी कारण से जयराम के कार्यकाल में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गयी थी। यह मामला उच्च न्यायालय में अब तक लंबित चल रहा है। दूसरी ओर जो एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसे 2017 में असम के मामले के साथ टैग करके जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि राज्य विधायिका को ऐसा अधिनियम पारित करने का अधिकार

ही नहीं है।

अब प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के विवाफ तीन याचिकाएं लंबित चल रही हैं। स्मरणीय है कि मंत्रिमण्डलों का आकार जब-जब राजनीतिक कारणों से आवश्यकता से अधिक बड़ा होने लगा और इस पर जनता में आवाज़ उठने लगी तब संसद ने एक संविधान संशोधन लाकर मंत्रिमण्डल के आकार की सीमा तय कर दी थी। उस सीमा के

अनुसार हिमाचल में अधिक से अधिक मुख्यमंत्री सहित केवल 12 मंत्री हो सकते हैं। इस समय सुकरू मंत्रिमण्डल में मंत्रियों के तो तीन पद खाली चल रहे हैं। जबकि छः मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त कर रखे हैं। इन नियुक्तियों को चुनौती देती हुई तीन याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही हैं। एक याचिका भाजपा के एक दर्जन विधायिकों द्वारा दायर की गई है। माना जा रहा है कि यह याचिका

भाजपा हाईकमान के अनुमोदन के बाद ही डाली गई है। निश्चित है कि भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले इस मामले में फैसला आने का प्रयास करेगी। यह भी तय है कि यह फैसला आने के बाद सरकार और कांग्रेस संगठन के समीकरणों में बदलाव आयेगा। लोकसभा चुनावों के लिये भी सत्ता के इस तरह के उपयोग का मामला एक मुद्दा बनेगा। क्योंकि यह सवाल उठेगा कि जब प्रदेश में ऐसा पूर्व में भी घट चुका था और भाजपा ने इसी कारण से ऐसी नियुक्तियां नहीं की थी तो सुकरू सरकार को कठिन वित्तीय स्थितियों में भी ऐसी नियुक्तियां करने की राजनीतिक आवश्यकता क्यों खड़ी हो गई थी? आज नेता प्रतिपक्ष तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि छः विधायिकों का भविष्य जानबूझकर दाव पर लगा दिया गया है। अब प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला आने में भी लम्बा समय लगने की संभावना नहीं मानी जा रही है। यह फैसला आने का सुकरू सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा इस पर शिमला से लेकर दिल्ली तक सबकी नज़रें लग गयी हैं।

क्या इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बंद होगा?

नियामक आयोग के नोटिस से उभरी चर्चा

विश्वविद्यालय की रही है।

चम्बा से एक अजय कुमार ने निजी क्षेत्र में खुले विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखते हुये इस संबंध में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम इस संबंध में शिकायतों दायर करने का अभियान जारी रखा। अब इन शिकायतों पर बाकायदा मामला दर्ज करके इस संबंध में कारवाई शुरू कर दी है। इसमें नियामक आयोग ने अजय कुमार बनाम इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय प्रकरण में विधिवत मामला दर्ज करके अगली कारवाई शुरू कर दी है। जिस पर 20 नवम्बर के लिए विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में खुले और भी विश्वविद्यालयों की कारगुजारीयों पर अब जनता नजर रखने लग पड़ी

है। क्योंकि हर विश्वविद्यालय की संचालन समिति में विधानसभा द्वारा कुछ विधायक भी नामित रहते हैं। इस परिषेक में इंडस

इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद और भी कई मामले खुलने की संभावना आने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह है नोटिस



HIMACHAL PRADESH
PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS REGULATORY COMMISSION
HAPPY NEST BUILDING, KAGNADHAR, BELOW BCS, SHIMLA-9
Phone No. +91-177-2673665, 2673664 Fax: +91-177-2673663 Email: secy-perc@nic.in

No. HP-PERC/Case No. 19/2023/3221

Dated: 8/11/23

Registered /Email

NOTICE

Take notice that Case No. 19 of 2023 has been instituted titled as Ajay Kumar V/s Indus International University" and will be heard on 20.11.2023 at 11:00 AM before the Hon'ble Commission.

You are therefore directed to appear in person along with relevant record before the Commission on aforesaid date & time. A copy of complaint enclosed herewith for your reference.

Further, if you fail to appear before the Commission on aforesaid date and time, the matter will be heard ex parte.
Authorised to issue notice by Ld. Commission.

Secretary
H.P. Private Educational Institutions
Regulatory Commission